सीमाओं की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण उतनी ही जरूरी है डेटा सुरक्षा : मुख्यमंत्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में डेटा सबसे मूल्यवान संपत्ति बन चुका है और इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साइबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं, इसलिए सरकार को समय के अनुरूप सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा।

मुख्यमंत्री सोमवार को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित 'राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने' विषयक कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध, डीप फेक और डिजिटल माध्यमों से बढ़ते खतरों को देखते हुए जागरूकता और तकनीकी क्षमता दोनों का विकास आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की सुरक्षा को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से यह केंद्र विकसित किया जाएगा। यह केंद्र साइबर सुरक्षा अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उभरते साइबर खतरों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ नागरिकों के व्यक्तिगत, वित्तीय और शासकीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। जनधन खाते, डीबीटी और यूपीआई जैसी व्यवस्थाओं ने आम नागरिकों तक सीधे लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वास बनाए रखने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के कारण यदि किसी नागरिक की जीवनभर की कमाई क्षणभर में समाप्त हो जाए तो यह अत्यंत गंभीर स्थिति होती है। इसलिए साइबर अपराधों की रोकथाम, समय पर पहचान और प्रभावी प्रतिक्रिया व्यवस्था विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डेटा ब्रीच की स्थिति में आर्थिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, इसलिए सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है।

मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा कल से

▸▸ परीक्षा केन्द्र पर ही ऑन स्पॉट प्रिंट होंगे प्रश्न पत्र, प्रदेश में बनाए गए 2 हजार 795 परीक्षा केंद्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुनः परीक्षा 16 जून से शुरू हो रही है। यह 23 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदेश भर में कुल 2 हजार 795 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा में लगभग 1 लाख 17 हजार से अधिक एवं कक्षा 8वीं के लगभग 1 लाख 32 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं और पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा सत्र 2025-26 का आयोजन 16 से 23 जून 2026 की अवधि में किया जाएगा।

परीक्षा केंद्रों पर ही होगा प्रश्न पत्रों का स्थल मुद्रण : पुनःपरीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रश्नपत्रों की ऑन स्पॉट प्रिंटिंग परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा की जाएगी। परीक्षा पोर्टल से प्रश्नपत्रों को डाउनलोड एवं प्रिंट करने के लिए जिला परियोजना समन्वयक को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

जन शिक्षा केन्द्र स्तर बनाए गए हैं परीक्षा केन्द्र : कक्षा 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षा के लिए केवल जनशिक्षा केन्द्र स्तर ही परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं। अगर किसी जिले में किसी परीक्षा केन्द्र पर 500 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हों तो उस स्थिति में राज्य शिक्षा केन्द्र से अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।

परीक्षार्थियों को शाला प्रमुख पहुंचाएंगे परीक्षा केन्द्र तक : पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला प्रमुख/शिक्षक को सौंपा गया है।

मध्यप्रदेश ने जीती राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप

39 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना प्रदेश, खातेगांव की बेटियों ने भी दिखाया दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब-जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। 12 से 14 जून तक आयोजित प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश ने कुल 39 पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित की।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 25 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य पदक अर्जित किए। इस प्रदर्शन के दम पर प्रदेश ने जूनियर पुरुष, जूनियर महिला, सब-जूनियर बालक और सब-जूनियर बालिका वर्ग में चैंपियनशिप का खिताब जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। जूनियर वर्ग की 1000 मीटर और 500 मीटर स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने 24 पदक हासिल किए, जिनमें 16 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य शामिल हैं। वहीं सब-जूनियर वर्ग की 500 मीटर और 200 मीटर स्पर्धाओं में 15 पदक मिले, जिनमें 9 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।

देवास जिले के खातेगांव की बेटियों ने भी प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। माही साहू ने जूनियर वर्ग की 500 मीटर सी-4 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दिव्यानी जाट ने सी-2 500 मीटर और सी-4 1000 मीटर स्पर्धाओं में दो रजत पदक अपने नाम किए। भाग्यश्री साहू ने के-4 200 मीटर स्पर्धा में रजत तथा के-2 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में एग्री-सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा, जर्मन सहयोग से हुआ एमओयू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में कृषि और सौर ऊर्जा के संयुक्त विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य सरकार ने जर्मन सहयोग से एग्री-वोल्टाइक परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मप्र ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इंडो-जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग परियोजना के बीच यह समझौता मंत्रालय में संपन्न हुआ। इस पहल का उद्देश्य कृषि भूमि का दोहरा उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे किसान अपनी जमीन पर खेती के साथ-साथ सौर ऊर्जा उत्पादन भी कर सकें। इससे अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम होगी, खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। समझौते के तहत जर्मन संस्था जीआईजेड और इंडो-जर्मन एग्री वोल्टाइक परियोजना राज्य में एग्री-वोल्टाइक परियोजनाओं की पहचान, तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन, डिजाइन, वित्तीय व्यवहार्यता तथा क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगी। इसके साथ ही किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, ऊर्जा विकासकर्ताओं और विद्युत वितरण कंपनियों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यह पहल प्रधानमंत्री कुसुम 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं के अनुरूप राज्य में कृषि और स्वच्छ ऊर्जा के समन्वित विकास को गति देगी।एमओयू मई 2030 तक प्रभावी रहेगा। इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक अमनवीर सिंह बैंस तथा जर्मनी और भारत के संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ग्लोबल विंड डे पर मध्यप्रदेश को मिला नवकरणीय ऊर्जा अवसंरचना उत्कृष्टता सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ग्लोबल विंड डे 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश को उभरती नवकरणीय ऊर्जा अवसंरचना उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया। गोवा में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह सम्मान प्रदेश के ऊर्जा सचिव विशेष गढ़पाले को प्रदान किया। 'पवन ऊर्जाः महत्वाकांक्षा से तीव्र क्रियान्वयन तक' विषय पर आयोजित सम्मेलन में देशभर के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, डिस्कॉम प्रतिनिधि, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी तथा उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी तथा विभिन्न पवन ऊर्जा संगठनों के सहयोग से किया गया। सम्मेलन में भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया में पवन ऊर्जा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक विकास को गति देने और हरित रोजगार के नए अवसर सृजित करने में पवन ऊर्जा के योगदान पर विचार-विमर्श हुआ।

अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में एमएसएमई अधिकारी ने किया भारत का प्रतिनिधित्व

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की सहायक संचालक ओजस्वी टेंभरे ने सिंगापुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। सिंगापुर सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 'ट्रेड बिजनेस डेवलपमेंट' विषयक इस प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत से केवल एक प्रतिभागी का चयन किया गया था। आठ से 12 जून तक सिंगापुर के सिविल सर्विस कॉलेज में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्व के लगभग 25 देशों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार एवं व्यवसाय विकास, निवेश संवर्धन, उद्यमिता, नवाचार और वैश्विक सहयोग से जुड़ी सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणालियों से प्रतिभागियों को अवगत कराना था।

प्रशिक्षण के दौरान ओजस्वी टेंभरे ने मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के प्रसिद्ध 'शिवपुरी जैकेट' को सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को स्मृति-चिह्न के रूप में भेंट किया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों के कौशल, एक जिला-एक उत्पाद योजना तथा प्रदेश में स्थानीय उत्पादों के संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी साझा की। इस पहल के माध्यम से मध्यप्रदेश की हस्तशिल्प परंपरा और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादकः डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादकः अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com